

### Housing facility to husband and wife employees

3227. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether in case of both husband and wife being Railway employees and only one housing facility provided for both, the other spouse is granted housing allowance;

(b) if so, details thereabout; and

(c) if not, reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The intention in not granting house rent allowance where one of the spouses is allotted accommodation, is that he/she is expected to live in that accommodation with his/her family and the other spouse is not expected to incur any expenditure for the rent of the accommodation. This rule is common for all Central Government employees.

### Settlement of Departmental cases outside Court

3228. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large number of cases have been filed by aggrieved regarding employees being frustrated by not getting departmental remedy resulting in unnecessary litigation;

(b) the functions of the Law Department and Senior Law Officer attached to Zonal Headquarters;

(c) whether the opinion of the Law Officers is taken in each case for its settlement outside the Court or for contesting according to the merit of the case to avoid unnecessary litigations

and wastage of public money; and

(d) policy of the Govt. in aforesaid matter of litigations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No, Sir.

(b) The Senior Law Officer or the Law Officer as the case may be and the Law Department of a Zonal Railway deal with the legal work on the advisory side and commercial cases except claim cases, refund of freight/fare and claim compensation cases arising out of accident to trains. All court cases involving a Zonal Railway are also taken care of by its Law Department, under the overall supervision of its Law Officer/Senior Law Officer.

(c) Opinion of the Railway Law Officer concerned is obtained whenever the legality of contesting a cases in court or settling it outside the court is under consideration.

(d) The policy of the Government is not to involve in unnecessary litigation.

### Cases filed by Railwaymen of Eastern, Southern and South-Central Railways

3229. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) number of cases filed by Railway workers of Eastern, Southern and South-Central Railways under Section 33 C(2) of I.D. Act, 1947 in different Central Government labour courts from January, 1981 to June, 1982; and

(b) reasons and justifications for not settling the cases outside the Courts by negotiation to avoid unnecessary wastage of National Exchequer?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Information

is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

### सस्ती किताबों का प्रकाशन

3231. श्री कुम्भा राम आर्य : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय स्तर की सस्ती किताबें और विदेशी किताबें प्रकाशित करने के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशित किताबों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या किताबों का बाजार में बेचा गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० खूंगन) : (क) से (ग). अपने विश्व-विद्यालयों के छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के सस्ते संस्करणों तथा मूल रूप से विदेशों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन कार्यक्रम इंग्लैंड (अंग्रेजी भाषा पुस्तक सोसाइटी श्रृंखला, 1960 से) अमेरिका, (संयुक्त भारत अमेरिका का मानक पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम 1961 से) तथा सोवियत रूस (संयुक्त भारत-सोवियत पाठ्य पुस्तक कार्यक्रम 1965 से) की सरकारों के सहयोग से संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी तीनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकें भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय आदि जैसी

विशेषज्ञ एजेंसियों के परामर्श से अनुमोदित की जाती है। पुस्तकों का मूल्यांकन सामान्यतः छात्रों के लिये उनकी उपयुक्तता तथा उपयोगिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर किया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जाते हैं कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत केवल स्वीकृत पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों को ही पुनः प्रकाशित किया जाए। इंग्लैंड तथा सोवियत रूस कार्यक्रमों के अन्तर्गत पुस्तकें संबंधित देशों के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है तथा उन्हें भारत में सामान्य व्यापार माध्यमों के जरिये आयातित किया और बेचा जाता है। भारत अमेरिका कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय प्रकाशकों द्वारा चुनो हुई पुस्तकें कम कीमत के संस्करणों में संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय संचार एजेंसी की उपयुक्त आर्थिक सहायता से प्रकाशित की जाती है और सामान्यतः व्यापार माध्यम के जरिये उन्हें बेचा जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक लगभग इंग्लैंड को 714 पुस्तकें, अमेरिका को 1620 पुस्तकें और सोवियत रूस को 410 पुस्तकें कम कीमत के संस्करणों में प्रकाशित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, जो इस मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत्त संगठन है, 1970 से एक योजना चलाता है ताकि भारतीय लेखकों द्वारा अंग्रेजी में विश्व विद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके जिन्हें अन्तर्गत भारतीय लेखन को प्रोत्साहित करने तथा विश्वविद्यालय स्तर की अंग्रेजी पुस्तकें कम कीमतों पर